



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2019



**प्रयोग समाज सेवी संस्था
तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़**

पृष्ठभूमि -

प्रयोग समाज सेवी संस्था की स्थापना वर्ष 1975 से आरंभ हुआ और पंजीयन वर्ष 1982 में हुआ। प्रयोग की पहचान एक ऐसे संस्था के रूप में रही है जिसने ग्रामीण नेतृत्व को विकसित किया है। प्रयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी और वंचित समुदाय के युवक युवतियों के लिए 'गांधीयन एक्टीविज्म स्कूल' के रूप में केन्द्र को विकसित किया है। अभी तक 2000 से भी ज्यादा युवाओं को जमीनी कार्यकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया गया है जो राज्यभर में कार्यरत हैं।

संस्था द्वारा दलित, आदिवासी एवं भूमिहीनों के लिये किये गये प्रमुख कार्य निम्नानुसार है -

- आदिवासी और भूमिहीनों को संगठित और एकजुट करना तथा स्थानीय ग्रामीण नेतृत्व और सामुदायिक संगठनों को मजबूत बनाना।
- शासकीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन की दिशा में जागरूक करना ताकि अधिकाधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।
- महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन व अपने अधिकारों के प्रति सामूहिक प्रयास करना।
- संघर्ष, रचना व संवाद के माध्यम से अधिकारों के लिए जागरूक करना।
- समुदाय के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा जल, जंगल, जमीन व आजीविका के अधिकार के लिए सामूहिक पहल करना।
- जागरूकता निर्माण और मोबिलाईजेशन के विभिन्न पहलुओं जैसे लोक केन्द्रित विकास के लिए जवाबदेह संसाधन प्रबंधन, भूमि वितरण, आदिवासी समाज की जंगल में पहुंच (उपयोग-उपभोग), विकेन्द्रिकृत निर्णयों और सामाजिक राजनैतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।

संस्थागत कार्यक्षेत्र

संस्था द्वारा वर्ष 2018 में चार राज्यों में व्यापक तौर पर संगठन निर्माण, युवा एवं महिला नेतृत्व निर्माण, शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन तथा अधिकाधिक हितग्राहियों को खाद्यान्न आपूर्ति व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने तथा कार्यक्षेत्र में संचालित समुदाय आधारित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से "राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद का गठन" तथा "आवासीय भूमि अधिकार कानून" को लागू करने जैसे नीतिगत बदलाव की दिशा में प्रयास कर रही है।

राज्यवार कार्यक्षेत्र का विवरण -

क्र.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लॉक संख्या	पंचायत संख्या	गांव संख्या		
					सघन	सम्पर्क	कुल
1	छत्तीसगढ़	18	23	393	439	292	731
2	मध्यप्रदेश	18	43	472	472	314	786
3	उड़ीसा	09	14	75	225	150	375
4	झारखण्ड	08	16	58	145	97	242
5	बिहार	04					
6	तमिलनाडु	02					
		51	96	998	1281	853	2134

संस्था द्वारा संचालित परियोजनाएँ का वर्ष 2019 की संक्षिप्त जानकारी-

1. यूरोपिन यूनियन व डब्ल्यू.एच.एच., नई दिल्ली के सहयोग से संगठन निर्माण परियोजना का यह अंतिम वर्ष था, जो वर्ष 2016 से संचालित होकर वर्ष 2019 में चार वर्ष पूरा कर रहा है। इस परियोजना का यह वर्ष उपलब्धियों को एकत्रित करना तथा मूल्यांकन व अंतिम परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। परियोजना की मूल गतिविधियों के अलावा इस वर्ष बजट को संशोधित किया गया है।
2. जर्मन कापरेशन व डब्ल्यू.एच.एच. नई दिल्ली के सहयोग से इस वर्ष नई परियोजना का शुभारंभ हुआ है, जिसे भूमि और जल अधिकार परियोजना कहा गया है।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं का संकलित गतिविधियाँ निम्नानुसार है -

- **महिला सशक्तिकरण सम्मेलन** - परियोजना क्षेत्र के पूरे 50 जिलों में 42 जिलों में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 4568 महिला तथा 1582 पुरुषों ने भागीदारी किया। राज्यवार प्रतिभागियों की जानकारी इस प्रकार है :-

क्र.	राज्य	जिलों की संख्या	सहभागिता		
			महिला	पुरुष	कुल
1	मध्यप्रदेश	14 ग्वालियर, शिवपुरी, विदिशा, उमरिया, दमोह, मुरैना, श्योपुर, सागर, टीकमगढ़, शहडोल, जबलपुर, सिवनी, सिहोर, झाबुआ	1200	215	1415
2	छत्तीसगढ़	14 नारायणपुर, महासमुन्द, बलरामपुर, राजनांदगांव, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, रायगढ़, मुंगेली	1823	1000	2823

3	उड़ीसा	8 कालाहण्डी, कंधमाल, सुन्दरगढ़, रायगड़ा, खुर्दा, बालोंगीर, जाजपुर, नयागढ़	934	279	1213
4	झारखण्ड	6 पलामू, चतरा, गुमला, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग	611	88	699
			4568	1582	6150

- **युवा उन्मुखीकरण कार्यशाला** - वर्ष 2016 से 2017 के दौरान 4 राज्यों के 50 जिलों में आयोजित युवा उन्मुखीकरण शिविर से चयनित 50 युवाओं को उन्मुखीकरण कार्यशाला किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य आगामी समय में कलस्टर स्तर पर होने वाले युवा उन्मुखीकरण कार्यशाला को सहयोग करने तथा अपने कायक्षेत्र के गांवों में संगठन को सशक्त कर जल, जंगल, जमीन तथा आजीविका के अधिकार के लिए अहिंसात्मक तरीके से पहल कर सके और हितधारकों को अधिकार दिला सके।
- **युवा उन्मुखीकरण कार्यशाला** - प्रत्येक जिले से चयनित 10 युवाओं को उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन कलस्टर स्तर पर किया गया, जिसमें प्रत्येक जिला स्तर पर युवा वर्ग संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर संगठनात्मक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने तथा अपने अधिकार की दिशा में किये जा रहे प्रयास में अपना योगदान दे सके व गांव को अहिंसात्मक गतिविधियों के माध्यम से भयमुक्त, भूखमुक्त व शोषण मुक्त समाज की रचना की दिशा में अग्रसर कर सके।

इस वर्ष परियोजना क्षेत्र के 4 राज्यों में 6 कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो इस प्रकार है -

राज्य	जिला	स्थान	अवधि	सहभागिता			
				गांव सं.	महिला	पुरुष	कुल
झारखण्ड	हजारीबाग	हजारीबाग	17-18 जून 2019	25	20	35	55
छत्तीसगढ़	कोरिया	जरडोल	21-23 जून 2019	16	32	55	87
मध्यप्रदेश	मुरैना	जौरा	28-30 जून 2019	18	53	44	97
मध्यप्रदेश	सिहोर	भोपाल	27-28 अगस्त 2019	18	29	44	73
उड़ीसा	कालाहण्डी	भवानी पटना	16-17 सितम्बर 2019	14	38	45	83
छत्तीसगढ़	बलौदा बाजार	तिल्दा	22-25 सितम्बर 2019	12	35	35	70
मध्यप्रदेश	मुरैना	जौरा	10-11 अक्टूबर 2019	53	38	61	99
मध्यप्रदेश	जबलपुर	मोहला	19-20 अक्टूबर 2019	13	56	32	88
मध्यप्रदेश	विदिशा	गंजबसोदा	14-15 नवम्बर 2019	41	61	39	100

छत्तीसगढ़	कोण्डागांव	पाटला	28-30 दिसम्बर 2019	14	30	55	85
कुल				224	392	445	837

- सरकारी लाईन विभाग के साथ जिला स्तरीय इन्टरफेस कार्यक्रम - वर्ष 2019 के लिए इस परियोजना के तहत निर्धारित जिले - छत्तीसगढ़ के 7 जिले, मध्यप्रदेश के 8 जिले, उड़ीसा के 9 जिले तथा झारखण्ड के 6 जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के चयनित 20 मुखियाओं का दल द्वारा अपने मुद्दों के समाधान के लिए जिला स्तर के अधिकारियों के साथ संवाद किया गया तथा समस्याओं के समाधान के लिए शासन की ओर से आश्वासन प्राप्त किये ।

वर्ष 2019 के दौरान 12 इन्टरफेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका राज्यवार स्थिति इस प्रकार है -

राज्य	जिला	सहभागिता			
		गांव सं.	महिला	पुरुष	कुल
झारखण्ड	2 हजारीबाग, धनबाद	30	290	120	410
उड़ीसा	4 कंधमाल, कालाहण्डी, खुर्दा, रायगड़ा	32	29	83	112
मध्यप्रदेश	5 शिवपुरी, दमोह, मुरैना, सिहोर, सागर	216	523	527	1050
छत्तीसगढ़	4 बलरामपुर, बलौदाबाजार, नारायणपुर, जशपुर	21	18	55	73
बिहार	1 गया	25	95	115	210
		324	955	900	1855

(विस्तृत रिपोर्ट परियोजना रिपोर्ट में उपलब्ध है)

- गांव स्तरीय माइक्रोप्लान प्रशिक्षण - 30 जिलों के चयनित 1 मुखिया साथी तथा प्रत्येक जिले के जिला समन्वयकों के लिए 3 दिवसीय गांव स्तरीय माइक्रोप्लान प्रशिक्षण का आयोजन प्रयोग आश्रम तिल्दा में संगठन निर्माण परियोजना के लिए 29 से 31 मई 2019 तथा भूमि और जल अधिकार परियोजना के लिए 1 से 3 जून 2019 तक किया गया, जिसमें गांव स्तर पर समस्याओं को विभिन्न तरह से चित्रण कर प्राथमिकता के क्रम में बनाकर ग्रामसभा में अनुमोदित कराकर स्थानीय प्रशासन के साथ पहल करने पर प्रशिक्षित किया गया ।
- कृषि में सुधार पर कृषक प्रशिक्षण - परियोजना क्षेत्र के पूरे 30 जिलों में कृषि में सुधार, कम लागत खेती, मिश्रित खेती तथा खेती से जुड़े हुए पारम्परिक प्रथाओं पर प्रत्येक जिले के 20 चयनित किसानों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कृषक भाईयों का अपने

महत्वपूर्ण अनुभव को साझा किया गया ताकि खेती को घाटे का सौदा न बनाकर उपजाऊ व आयवर्धक खेती बनाया जा सके ।

वर्ष के दौरान 23 प्रशिक्षण आयोजित किया जा सका है, जिसकी राज्यवार स्थिति इस प्रकार है -

राज्य	जिला	सहभागिता			
		गांव सं.	महिला	पुरुष	कुल
झारखण्ड	4 पलामू, धनबाद, चतरा, हजारीबाग + कोडरमा	76	124	125	249
उड़ीसा	4 बालोंगीर+कालाहण्डी, खुर्दा, सुन्दरगढ़, रायगड़ा+कंधमाल	46	82	158	240
मध्यप्रदेश	3 शिवपुरी, दमोह, विदिशा	56	44	91	135
छत्तीसगढ़	5 बलरामपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, मुंगेली, नारायणपुर	23	31	115	146
		201	281	489	770

- **जन-सुनवाई कार्यक्रम** - परियोजना क्षेत्र के पूरे 30 जिलों में जन-सुनवाई का कार्यक्रम कर शासन-प्रशासन के साथ अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए जनता के मध्य जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर निराकरण की दिशा में आम जनता के सामने शासन-प्रशासन की बाध्यता को स्पष्ट करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है । जिसके तहत इस वर्ष 7 जिलों में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा सका, जो राज्यवार इस प्रकार है -

राज्य	जिला	सहभागिता			
		गांव सं.	महिला	पुरुष	कुल
झारखण्ड	3 पलामू, धनबाद, हजारीबाग	55	578	370	948
मध्यप्रदेश	4 ग्वालियर, शिवपुरी, दमोह, विदिशा	87	192	260	452
		142	770	630	1400

- **राज्य स्तरीय संगोष्ठी** - इस वर्ष चारों राज्यों के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी का प्रावधान किया गया था, जिसमें तीन राज्यों में - उड़ीसा राज्य के अन्तर्गत कालाहण्डी जिले के भवानीपटना में 18 अगस्त 2019 को तथा मध्यप्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल में 27 नवम्बर 2019 को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जय जगत 2020 की तैयारी पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया गया ।

- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन्दौर की शिल्पा बहन के साथ अनुबंध किया गया है, जिसमें दिसम्बर 2019 तक पूरा कर लिया जायेगा ।
- विडियो डाक्यूमेंटेशन - 4 वर्ष के परियोजना गतिविधियों के दौरान तैयार किये गये मॉडल गांव में से चयनित 10 मॉडल का विडियो डाक्यूमेंटेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें बेस्ट प्रेक्टिसेस जैसे- भूमिहीन आदिवासियों को भूमि का अधिकार, आजीविका के लिए तालाब का नवीनीकरण, उद्यमिता के लिए मछली पालन, टेण्ट किराया व बस का संचालन, भूमि अधिकार के बाद आदिवासियों द्वारा जैविक खेती का प्रयोग, युवा नेतृत्व तैयार करना, सामुदायिक स्वैच्छिक कार्यक्रम- श्रमदान के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रम, ग्रामकोष व अनाजकोष तथा प्रशासनिक जनवकालत आदि शामिल होगा । यह कार्यक्रम परियोजना के लिए विस्तारित अवधि- जनवरी से जून 2020 के दौरान किया जायेगा ।
- भूमि अधिकार** - वर्ष 2019 के दौरान उड़ीसा राज्य के खुर्दा, नयागढ़ तथा कंधमाल जिले में कृषि तथा आवासीय भूमि अधिकार प्राप्त हुए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है -

भूमि के प्रकार	राज्य	जिला	गांव संख्या	परिवार संख्या	रकबा	अनुमानित कीमत	
कृषि भूमि अधिकार	उड़ीसा	खुर्दा	4	144	11.890	718100.00	
		नयागढ़	5	62	107.000	7490000.00	
		कंधमाल	1	5	2.500	250000.00	
	मध्यप्रदेश	श्योपुर	1	87	217.50	174000000.00	
		मुरैना	1	21	52.20	52200000.00	
	छत्तीसगढ़	कोरिया	3	25	37.87	2286200.00	
		सूरजपुर	8	30	35.40	3650000.00	
		जशपुर	24	460	1052.00	105200000.00	
				47	834	1516.36	345794300.00
	आवासीय भूमि अधिकार	उड़ीसा	कंधमाल	13	119	2.481	1240500.00

- सामूहिक रचनात्मक गतिविधि** - समुदाय द्वारा भूमि विकास तथा जल संरक्षण की दिशा में सामूहिक प्रयास किया जाता है तथा अपने गांव के आस-पास में संगठन तथा गांव के सहयोग से रचनात्मक कार्य कर कच्चा सड़क निर्माण, सामूहिक खेती, तालाब गहरीकरण, कच्चा चेक डेम निर्माण आदि किया जाता है । वर्ष 2019 के दौरान किये गये रचनात्मक कार्य का विवरण इस प्रकार है -

कार्य का विवरण	राज्य	जिला	गांव संख्या	लोगों की सहभागिता	कुल कार्य दिवस	अनुमानित श्रमदान (रु. में)
कच्चा सड़क निर्माण	उड़ीसा	रायगड़ा, कंधमाल, खुर्दा, जाजपुर, सुन्दरगढ़	7	287	735	129,360.00
	बिहार	नवादा	1	28	28	4,872.00
सामूहिक खेती	उड़ीसा	पुरी	1	120	30	5,280.00
तालाब गहरीकरण	झारखण्ड	धनबाद	1	35	735	129,360.00
	उड़ीसा	खुर्दा	1	48	48	8,448.00
	मध्यप्रदेश	श्यापुर	1	150	1125	195,750.00
चेक डेम निर्माण	उड़ीसा	नयागढ़	1	42	168	29,568.00
	झारखण्ड	पलामू	1	500	2500	440,000.00
	मध्यप्रदेश	सिहोर	1	70	245	42,630.00
पौधरोपण	मध्यप्रदेश	मुरैना	1	50	25	4,350.00
वर्मी कम्पोस्ट	मध्यप्रदेश	सिहोर	1	16	40	6,960.00
कुँआ सफाई	मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	1	55	550	95,700.00
	बिहार	नवादा	1	5	75	1,305.00
पाईन वाटर सोर्स	बिहार	नवादा	1	25	75	13,050.00
कुल			20	1431	6379	11,06,633.00

- **संगठनात्मक सशक्तिकरण** - इसके तहत संगठन को सशक्त रूप से संचालित करने के लिए कमेटी का गठन करना, सदस्यता निर्माण, मुखियाओं का चयन, अनाजकोष तथा ग्रामकोष का निर्माण करना है, जिसका राज्यवार स्थिति इस प्रकार है -

गतिविधियाँ	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	उड़ीसा	झारखण्ड	बिहार	तमिल नाडु	कुल
गांव की संख्या	786	703	375	282	80	40	2266
कमेटी का गठन	629	562	300	208	45	27	1771
सदस्यता निर्माण	23039	16862	6442	8941	705	342	56331
ग्रामीण मुखिया का चयन	1258	1124	600	564	160	80	3786
युवा नेतृत्व प्रशिक्षण	19	18	9	6	0	0	52
ग्रामकोष (गांव संख्या)	579	510	339	209	45	27	1709
अनाज कोष (क्विंटल में)	448.88	404.57	221.33	158.60	24.40	6.50	1264.28

3. यूरोपिन यूनियन व डब्ल्यू.एच.एच., नई दिल्ली के सहयोग से प्रयोग आश्रम के केम्पस में “ट्राईबल रिसोर्स सेन्टर” बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इसे दिसम्बर 2019 तक पूरा कर लिया जायेगा।
4. आई.जी.एस.एस.एस., नई दिल्ली के सहयोग से “आजीविका के उत्थान का स्थायी विकल्प” परियोजना का क्रियान्वयन मार्च 2019 तक किया गया। अप्रैल 2019 से नये संदर्भ में एजेण्ट्री द्वारा सहयोग दिया जा रहा है उसका नाम “सुपोषण” रखा गया है, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होगा, मतलब अप्रैल 2019 से मार्च 2023 तक। इस परियोजना के अन्तर्गत अप्रैल से दिसम्बर 2019 तक निम्न-लिखित गतिविधियों का संचालन किया गया -
 - परियोजना के उद्देश्यों और परिणामों के संदर्भ में ग्राम स्तरीय बैठक
 - SAM/MAM बच्चे और खून की कमी वाली महिला व किशोरी बालिका के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन।
 - SAM/MAM बच्चे और खून की कमी वाली महिलाओं के लिए समूह का उन्मुखीकरण कार्यशाला।
 - ग्राम स्तरीय “पोषण वाहिनी” नाम से स्वयं सेवक का गठन करना।
 - अन्य हितधारक जैसे- ए डब्ल्यू डब्ल्यू, ए एन एम, आशा, एन आर सी ऑफिसियल्स, सी डी पी ओ तथा उद्यानिकी विभाग के साथ इन्फरफेस मीटिंग।
 - फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे- ए डब्ल्यू डब्ल्यू, ए एन एम, आशा आदि के साथ मासिक बैठक।
 - विशेष दिवस जैसे- दुग्धपान सप्ताह, पोषण सप्ताह का उत्सव के रूप में मनाना।
5. यूनिसेफ रायपुर के सहयोग से “शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009” पर अभियान जो कार्यक्रम इस वर्ष संचालित किये गये जिसमें पालक जागरूकता, शाला प्रबंधन समिति जागरूकता, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा का चर्चा, शाला प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना, बच्चों के लिए स्टडी कार्नर निर्मित कराना आदि शामिल रहा है।
6. “फाओ” इटली के सहयोग से कानूनी सलाह एवं संगोष्ठी कार्यक्रम।
7. “आदिवासी लाईव मेटर” कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़, त्रिपुरा तथा तमिलनाडु राज्य के आदिम जनजाति समुदाय के युवाओं को डिजिटल साक्षरता के लिए प्रशिक्षित करना तथा उनके स्वाभिमान तथा अधिकार के लिए लेखन कार्य तथा विडियोग्राफी सिखाकर विजुअल पहल करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस वर्ष उनको प्रशिक्षित करने की दिशा में कार्य किया गया।

(अरुण कुमार)
सचिव